SHRI BINOY VISWAM (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by Shri Rewati Raman Singh.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by Shri Rewati Raman Singh.

SPECIAL MENTIONS

Demand to declare the time period by when the daily wager will be given permanent job

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में कितने जवाहर नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं? विशेषकर उत्तराखण्ड के अंतर्गत हरिद्वार में ऐसे कितने विद्यालय हैं और उनमें कितने मैस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो पिछले 12-13 सालों से दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं? उन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है, इसके क्या कारण हैं? पूरे देश में चलने वाले जवाहर नवोदय विद्यालय की संख्या कितनी है, इनमें कितने मैस चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं और क्या इनको पूरे देश में एक जैसा वेतनमान दिया जाता है? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? इन विद्यालयों में अंशकालिक या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन लोगों को स्थायी नियुक्ति का आश्वासन भी समय-समय पर दिया जाता रहा है, लेकिन लम्बा समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इन मैस वेतन भोगियों को स्थायी नियुक्ति नहीं दी गयी है। इस तरह हमेशा इन लोगों के सामने रोजगार की समस्या बनी रहती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि पूरे देश में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें दैनिक वेतन भोगियों के रूप में पिछले 12-13 सालों से स्थायी नहीं किया गया है? कृपया राज्यवार ब्यौरा देने की कृपा करें। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन सभी कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति कब तक दी जाएगी?

MR. CHAIRMAN: Shri M.P. Veerendra Kumar; not present. Shri Elamaram Kareem.

Demand to increase remuneration of Mid-Day Meal workers

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Sir, nearly 26 lakh mid-day meal workers are working in 11.4 lakh schools feeding 12 crore children under School Mid-Day Meal Scheme under the Right to Food Act. In 2009 only, the Government of India started giving remuneration of ₹1,000 per month, that too for ten months only. Earlier, their payment was part of the cooking cost. They don't have any social security or pension. They do not get any medical benefit even though burn injuries are very common. Trade unions had been demanding minimum wages and pension. Reports of the CAG and the Planning Commission had recommended increase in remuneration to these workers. In

the 45th Indian Labour Conference, the Ministry of HRD has given a written assurance that it is considering the enhancement of honorarium of the mid-day meal cooks by ₹ 500 for the year 2013-14 and by ₹1,000 by 2014-15 to make it ₹ 2,000 by 2015-16. But since 2009, there has been no increase in their remuneration. Mid-day meal workers are mostly from socially-backward sections of the society and nearly 40 per cent of them are widows. So, the Government should urgently consider the matter of increasing the remuneration of mid-day meal workers.

Demand to improve train services connecting Etah in Uttar Pradesh

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): महोदय, उत्तर प्रदेश का एटा जनपद प्रदेश के अत्याधिक पिछड़े जनपदों में से है। पिछड़ेपन का मुख्य कारण है, एटा जिला मुख्यालय का किसी मुख्य रेल लाइन से जुड़ाव नहीं है। सन् 1964 में दिल्ली-टून्डला रेल लाइन पर स्थित छोटे से स्टेशन बरहन से एटा को जोड़ा गया था, जिस पर केवल एक पैसेन्जर रेलगाड़ी सुबह शाम आती जाती है।

एटा के नागरिकों का व्यापार, रोजगार, कृषि, शिक्षा आदि के लिए आगरा-दिल्ली-कानपुर के साथ विशेष संबंध रहता है। आगरा-दिल्ली तथा कानपुर के साथ रेल लाइन से जोड़ने हेतु एटा के हजारों नागरिकों ने अनेक बार आन्दोलन किए हैं। नागरिकों के व्यापक आन्दोलन के परिणामस्वरूप 2-3 वर्ष पूर्व रेल विभाग ने एटा से बरहन तक जाने वाली पैसेन्जर ट्रेन को आगरा तक विस्तारित कर फास्ट पैसेन्जर ट्रेन लगभग 6 माह चलाई, जिसके कारण एटा देहात, आगरा देहात के नागरिकों को काफी सुविधा महसूस हुई और रेल विभाग की आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई। परंतु अचानक ही एटा-आगरा फास्ट पैसेन्जर को पुन: बन्द कर दिया गया, जिसके कारण एटा के नागरिकों में भारी गुस्सा है और वे पुन: आन्दोलन करने पर उतारु हैं।

अत: मैं इस अवलिम्बनीय अत्यंत लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि एटा से आगरा तक सुपर फास्ट पैसेन्जर तथा एटा से कानपुर-इलाहाबाद व दिल्ली तक जाने के लिए एक-एक कोच किसी एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ने की कार्यवाही अविलम्ब की जाए।

Demand to include Dhangar tribe of Maharashtra in Scheduled Tribes list

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं आपका ध्यान 70 सालों से महाराष्ट्र के धनगर जनजाति पर होते आ रहे अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। संविधान द्वारा दी गई अनुसूचित जनजाति की सूची में 36 नम्बर पर होते हुए भी महाराष्ट्र की "धनगर" की जगह "धनगड" लिखे जाने की वजह से 70 सालों से धनगरों को ST (Scheduled Tribes) का आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। वर्ष 2013 से लगातार मैं इस विषय पर कार्य कर रहा हूं। भाजपा ही केवल ऐसी पार्टी रही है जो वर्ष 2013 से धनगरों का अनुसूचित जनजाति आरक्षण देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आदरणीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी एवं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री, देवेन्द्र फडणवीस जी इस विषय को गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन सच बात यह भी है कि इसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में धनगर समाज काफी नाराज़ है। उनके मन में यह भावना है कि उनके साथ धोखा हुआ है और जो वादा चुनावी घोषणा-पत्र में भाजपा सरकार ने किया था, जो लिखित